माननीय *अजीत सिंह बैंस* जे. के समक्ष

बुद्धि प्रकाश यादव, *याचिकाकर्ता*

बनाम

के.सी शर्मा और अन्य, - *उत्तरदाता।*

आपराधिक संशोधन सं. 1981 की 147

4 जून, 1981।

दंड प्रक्रिया संहिता (1974 का II) - धारा *197 (2), 200:* और *202* - लोक सेवकों के खिलाफ शिकायत - अभियुक्त को प्रक्रिया अभी तक जारी नहीं की गई है - ऐसे अभियुक्त - क्या उन्हें जांच कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है - गंभीर आरोप *लोक सेवकों के खिलाफ किए गए शिकायतकर्ताओं पर हमला करना, पीटना और दुर्व्यवहार करना - कथित अवैध कृत्यों और लोक सेवकों द्वारा आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के बीच कोई उचित संबंध नहीं है - मुकदमा चलाने की मंजूरी - यदि धारा* 197 (2) के तहत आवश्यक हो।

अदालत ने कहा कि शिकायत में नामित आरोपी को जांच के स्तर पर कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है। जांच के चरण में, ट्रायल कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह न केवल अनुपस्थित आरोपी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को न्याय के कटघरे में लाने की दृष्टि से भी सभी तथ्यों को प्राप्त करे, जिनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यदि तथ्यों पर ट्रायल कोर्ट पाता है कि शिकायत तुच्छ है, वह उस स्तर पर शिकायत को खारिज कर सकती है और यदि उसे लगता है कि *प्रथम दृष्टया* मामला बनता है, तो वह कानून के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। यदि आरोपी को जांच के स्तर पर कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो यह जांच को निराश करने के समान होगा। यदि आरोपियों को तलब किया जाता है, तो बाद के चरण में उनके लिए यह दलील देना खुला है कि यह कार्य उनके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था।

(पैरा 8)।

माना कि यदि कथित कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई सांठगांठ

या उचित संबंध नहीं है, तो मंजूरी का सवाल ही नहीं उठता है, जाहिर है, उत्तरदाताओं को सौंपे गए आधिकारिक कर्तव्यों और उनके द्वारा किए गए कथित कृत्यों के बीच कोई संबंध नहीं है। शिकायत के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं है, जिस पर इस स्तर पर विचार किया जाना है। शिकायत में लगाए गए आरोपों *से प्रथम दृष्टया* पता चलता है कि आरोपी अवैध कृत्यों में लिप्त थे, जिसे उनके आधिकारिक कर्तव्य के पालन में किए जाने का दावा नहीं माना जा सकता है। किसी लोक सेवक का यह आधिकारिक कर्तव्य नहीं हो सकता कि वह किसी व्यक्ति को पीट दे या उस पर हमला करे या उसे गाली दे। यह किसी भी लोक सेवक का कर्तव्य नहीं हो सकता है, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक का कर्तव्य तो दूर की बात है।

(पैरा 11, 17 और 18)।

श्री ओ.पी. गुप्ता, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नारनौल के 15 अक्टूबर, 1980 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका अदालत ने एस/श्री के.सी. शर्मा, उपायुक्त और एल.डी. नरवाल, पुलिस अधीक्षक और उनके खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया। जैसा कि प्रार्थना की गई थी, 5 दिसंबर, 1980 को शिकायतकर्ता के बयान और शेष अभियुक्तों के खिलाफ उसके प्रारंभिक साक्ष्य के लिए आएं।

याचिकाकर्ताओं की ओर *से अधिवक्ता डीएन रामपाल।*

उत्तरदाताओं के लिए *हरियाणा के एडवोकेट-जनरल यू.डी.*

निर्णय

अजीत सिंह बैंस, जे।

(एक) 1981 के इन दो आपराधिक संशोधनों संख्या 147 और 1981 के 234 को इस सामान्य निर्णय द्वारा एक साथ तय किया जाएगा क्योंकि ये एक ही घटना और ट्रायल कोर्ट के एक ही आदेश से उत्पन्न होते हैं।

(दो) इन याचिकाओं को जन्म देने वाले तथ्य इस प्रकार हैं:

(तीन) शिकायतकर्ता बुद्धि प्रकाश यादव और ओम प्रकाश दोनों रेवाड़ी में वकालत कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 324, 342, 504,

506, 147, 148, 140 और 120-बी के तहत अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराईं, जो नारनौल के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में लंबित हैं। आरोप है कि 20 फरवरी, 1980 को सूरत राम गिरदावर को श्री ओम प्रकाश, एडवोकेट के माध्यम से तहसील परिसर के भीतर अपने म्यूटेशन को मंजूरी दिलाने आए व्यक्तियों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और गिरदावर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) ने अवैध रूप से हस्तक्षेप किया था; जब शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) से कानून को अपना काम करने की अनुमति देने के लिए कहा; और यह कि उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उन्हें हिरासत में लेने की धमकी दी और उन्होंने शिकायतकर्ताओं के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराया।

(चार) 20 फरवरी, 1980 को, अधिवक्ताओं ने अनिश्चित काल के लिए उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) की अदालत में पेश नहीं होने का फैसला किया, जिसके परिणामस्वरूप वह और अधिक क्रोधित हो गए और उकसाने के बाद उनके, पटवारी संघ और उपायुक्त के साथ शामिल हो गए; 23 फरवरी, 1980 को शाम लगभग 4 बजे उपायुक्त के निमंत्रण पर शिकायतकर्ता और अन्य अधिवक्ता लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह पहुंचे और पाया कि उपखंड अधिकारी (सिविल) के साथ नायब-तहसीलदार और 60/70 व्यक्ति पुलिस अधीक्षक के साथ बड़ी संख्या में पुलिस के अलावा पहले से ही वहां मौजूद थे।

(पाँच) शिकायतकर्ताओं और अन्य अधिवक्ताओं, जिनकी संख्या 25 थी, ने उपायुक्त से पूछा कि जो कुछ भी किया गया था वह उनके निर्देशों के अनुसार किया गया था, लेकिन इसके बजाय इनाम के रूप में उनके खिलाफ एक झूठा मामला दर्ज किया गया था। आयुक्त ने ऊंची आवाज में कहा कि वे विभाग को बदनाम करने के लिए झूठ बोल रहे थे और वह उनकी वकील टाइप बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं थे और उन्हें अपने नापाक कृत्य के लिए परिणाम भुगतने होंगे; शिकायतकर्ताओं और उनके सहयोगियों ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि इस तरह

की बातचीत ऐसे उच्च अधिकारी के मुंह से वांछनीय नहीं होगी, जिसके परिणामस्वरूप सभी उत्तरदाता ओम, प्रकाश, एडवोकेट पर हमला किया और उसे मुट्ठियों और थप्पड़ों से पीटा और उसका काला कोट फाड़ दिया और उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया; कि राजिंदर प्रसाद सेठी ने ओम प्रकाश के सिर के बाल उखाड़ दिए; शर्मा ने ओम *प्रकाश और सतबीर सिंह के बाएं कूल्हे पर डंडा मारा, सब-इंस्पेक्टर* ने बाईं आंख पर डंडा मारा और बिशंभर नाथ बख्शी ने उनके दाहिने पैर के अंगूठे के जोड़ पर डंडा *मारा* और उपमंडल अधिकारी (सिविल) मोहिंदर प्रकाश ने मां द्वारा गालियां देने के बाद उनके दाहिने पैर पर जूते से लात मारी; कि सभी आरोपियों ने ओम को संयुक्त रूप से पीटा प्रकाश ने मुट्ठियों, थप्पड़ों और *डंडे* के साथ और किशन चंद शर्मा, उपायुक्त ने कहा कि गोली चलाई जानी चाहिए और वह परिणामों को देखेंगे कि उनके द्वारा कितने वकीलों को ठीक किया गया था; कि बुद्धि प्रकाश यादव को भी उत्तरदाताओं द्वारा पीटा गया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राव निहाल सिंह को भी पीटा और उनके साथ दुर्व्यवहार किया और पुलिस अधीक्षक लछमन दास नरवाल और उप-विभागीय अधिकारी (सिविल) मोहिंदर प्रकाश बिडलान ने भी उन्हें और उनके सहयोगियों को मां और बहन द्वारा गंदी गालियां दीं। इसके बाद, लछमन दास ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ता और उनके सहयोगियों की महिलाओं और बेटियों को शाम तक लाया जाना चाहिए क्योंकि अन्यथा उनकी सेवाएं नहीं रहेंगी और राम सिंह, धर्मपाल और अन्य अधिवक्ता और उनके क्लर्क जो मौके पर मौजूद थे, इस घटना के गवाह बने।

(छः)आगे यह आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता और अन्य सहयोगियों ओम प्रकाश और राव निहाल सिंह को वहां बैठाया गया और दो घंटे के बाद उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दिया गया और अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया। यह शिकायत 26 फरवरी, 1980 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। श्री के. सी. शर्मा, जिला मजिस्ट्रेट,

एल. डी. नरवाल, पुलिस अधीक्षक और मोहिंदर प्रकाश बिडलान, उप-मंडल (सिविल) ने शिकायत दर्ज होने के तीन दिन बाद 29 फरवरी, 1980 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। नारनौल के जिला अटॉर्नी और रेवाड़ी के अतिरिक्त जिला अटॉर्नी के माध्यम से कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के प्रावधानों के मद्देनजर अदालत को उनके खिलाफ किसी भी शिकायत पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस आवेदन को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 15 अक्टूबर, 1980 के अपने आदेश के तहत स्वीकार कर लिया था और सर्वश्री केसी शर्मा, उपायुक्त और एल डी नरवाल, पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया था और शेष अभियुक्तों के खिलाफ प्रारंभिक साक्ष्य के लिए मामले को स्थगित कर दिया गया था। यह वह आदेश है जिसे शिकायतकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई है।

(सात) इस मामले में दो सवाल उठते हैं- क्या प्रतिवादी उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को जिला अटॉर्नी के माध्यम से जांच के चरण में शामिल किया जा सकता है और दूसरा, क्या यहां हमले और कारावास के कथित कृत्य और कानून के तहत इन अधिकारियों पर लगाए गए कर्तव्य या अधिकार के बीच एक उचित संबंध या उचित संबंध था। कहा जा सकता है कि अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या इरादा करते हुए किया गया था और न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (2) के अनुपालन के बिना शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता था।

(आठ) जहां तक प्रथम प्रश्न का संबंध है, इसका उत्तर नकारात्मक रूप में दिया जाना चाहिए। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को जांच के चरण में कार्यवाही में शामिल होने का कोई अधिकार नहीं था>, जब ट्रायल कोर्ट द्वारा उर्लीमिनार साक्ष्य भी दर्ज नहीं किए गए थे। यहां तक कि ट्रायल कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं के वकील द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कहा है कि लोक अभियोजक अभियुक्त की ओर से पेश नहीं हो सके। मुकदमे के पूर्व भाग में लगाए गए आरोप उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध भी बहुत गंभीर हैं। मेरे विचार से, शिकायत में नामित अभियुक्तों को जांच के स्तर पर कार्यवाही में भाग लेने का कोई अधिकार

नहीं था। जांच के स्तर पर, यह ट्रायल कोर्ट का कर्तव्य है कि वह न केवल अनुपस्थित आरोपी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति को न्याय के कटघरे में लाने की दृष्टि से भी सभी तथ्यों को प्राप्त करे, जिसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं और यदि तथ्यों पर ट्रायल कोर्ट पाता है कि शिकायत तुच्छ है, यह उस स्तर पर शिकायत को खारिज कर सकता है यदि यह हो। पता चलता है कि *प्रथम दृष्टया* एक मामला बनता है। यह कानून के अनुसार आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यदि आरोपी को जांच के स्तर पर कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, यह जांच को निराश करने के समान होगा। यह मानने के बाद कि जांच के स्तर पर लोक अभियोजक के हस्तक्षेप की अनुमति देने के लिए कोई न्यायिक मिसाल नहीं है, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने लोक अभियोजक को पेश होने और आपत्तियां उठाने की अनुमति देने में कानूनी गलती की है। यदि आरोपियों को तलब किया जाता है, तो बाद के चरण में उनके लिए यह दलील देना खुला है कि यह कार्य उनके द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था।

(नौ) चंद्रो *देवइग सिंह* बनाम के.प्रकाश *के बारे में एक अन्य,* (1) में उनके लॉर्डशिप द्वारा निम्नानुसार देखा गया था: -

> "दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 16 की पूरी योजना से पता चलता है कि, एक आरोपी व्यक्ति तब तक तस्वीर में नहीं आता है जब तक कि प्रक्रिया जारी नहीं की जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा आयोजित किए जाने पर उसे उपस्थित होने से रोक दिया जाता है। वह या तो व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील या एजेंट के माध्यम से उपस्थित रहता है ताकि उसे सूचित किया जा सके कि क्या हो रहा है। लेकिन चूंकि विचार करने का अधिकार यह है कि क्या उन्हें आरोप का सामना करने के लिए बुलाया जाना चाहिए, इसलिए उनके पास कार्यवाही में भाग लेने के लिए कोई अधिकार नहीं है और न ही मजिस्ट्रेट के पास उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने का अधिकार

है। इसलिए, इससे यह स्पष्ट होगा कि मजिस्ट्रेट के लिए यह खुला नहीं होगा कि वह आरोपी के रूप में नामित व्यक्ति के कहने पर गवाहों को कोई सलाह दे, लेकिन जिसके खिलाफ प्रक्रिया जारी नहीं की गई है: न ही ऐसे व्यक्ति के कहने पर गवाहों से पूछताछ की जा सकती है। निस्संदेह, मजिस्ट्रेट स्वयं शिकायतकर्ता के समक्ष प्रस्तुत गवाहों से ऐसे प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र है क्योंकि वह न्याय के हित में उचित समझता है। लेकिन इससे आगे वह नहीं जा सकते।

सुप्रीम कोर्ट की पूर्वोक्त टिप्पणियों के अनुसार, यह स्पष्ट है कि "अभियुक्त अपने खिलाफ प्रक्रिया जारी होने से पहले कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। हालांकि, वह उपस्थित हो सकते हैं या उनके वकील कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। लेकिन उन्हें प्रक्रिया जारी होने से पहले किसी अन्य सवाल को पूछने या अन्य जानकारी लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस प्रकार, पहले प्रश्न का उत्तर निम्न में नकारात्मक यह है कि आरोपी व्यक्ति को उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी होने से पहले भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(दस) जहां तक दूसरे प्रश्न का संबंध है, इसका उत्तर भी नकारात्मक में दिया जा सकता है।

(ग्यारह) शिकायत में लगाए गए आरोपों से *प्रथम दृष्टया* पता चलता है कि आरोपी अवैध कृत्यों में लिप्त थे, जिसे उनके आधिकारिक ट्विटर के प्रदर्शन में किए गए कार्यों के रूप में नहीं माना जा सकता है। किसी लोक सेवक का यह आधिकारिक कर्तव्य नहीं हो सकता कि वह किसी व्यक्ति को पीट दे या उस पर हमला करे या उसे गाली दे। यह लोक सेवक का कर्तव्य तो नहीं हो सकता, न कि देनुव आयुक्त और पुलिस अधीक्षक का दुत्व। ये दोनों अधिकारी जिले में प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। वे लाव / और व्यवस्था और सामान्य प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। उपायुक्त जिले के समग्र प्रभारी हैं जिन्हें जनता की 1 वास्तविक शिकायतों को

सुनने और शांति बनाए रखने के लिए जिले में पवित्र दुत्व सौंपा गया है। पुलिस अधीक्षक कानून और व्यवस्था का संरक्षक भी है। सभी स्टेशन हाउस ऑफिसर और अन्य पुलिस अधिकारी उनके नियंत्रण में हैं। उन्हें यह देखना होगा कि कोई अराजकता न हो; ताकि अपराधियों को पकड़ा जाए और शांतिपूर्ण नागरिकों की रक्षा की जाए। यदि ऐसे पदों पर बैठे व्यक्ति स्वयं अराजकता में लिप्त होते हैं, अधिवक्ताओं और उनके परिवारों को पीटना और हमला करना शुरू कर देते हैं, तो इसका परिणाम अराजकता के रूप में सामने आएगा।

(बारह) दोनों, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक [लोक सेवक] हैं। वे सार्वजनिक मालिकों के रूप में व्यवहार नहीं कर सकते। उनकी हर गतिविधि लोगों की सेवा के लिए है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, उन्हें कानून के अनुसार और नागरिकों के कल्याण के लिए इसका पालन करना था। अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के दौरान लोक सेवकों का कर्तव्य अलग था। उस समय, उन्हें विदेशी शासकों के हितों की सेवा करनी थी, लेकिन अब वे एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य के लोक सेवक हैं। हमारा देश अभी भी अविकसित है और राज्य के हर अंग को नागरिकों के कल्याण की प्राप्ति के लिए जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए काम करना चाहिए। + वह आबादी का आधा हिस्सा अभी भी आश्रय, भोजन और न्यूनतम कपड़ों की बुनियादी जरूरतों से वंचित है। योजना आयोग के आंकड़ों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में, एक लोक सेवक को अपने कर्तव्य का निर्वहन इस तरह से करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा कि, वह योगदान दे कल्याण की ओर न कि अपने आचरण से लोगों के लिए और अधिक दुख जोड़ने की ओर। लोक सेवक बहुत विनम्र, सुन्न और चरवाहों की तरह रहने वाला और घोड़े की तरह काम करने वाला होता है। उसे एक जीवन जीना चाहिए *सात्विक* और राजा नहीं। लॉर्ड डेनिंग ने अपनी पुस्तक 'कानून की उचित प्रक्रिया' में पुलिस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की है-

हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करने में, पुलिस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अपने बचाव के लिए समाज को पुलिस के एक अच्छी तरह से नेतृत्व, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अच्छी तरह से अनुशासित बल की आवश्यकता होती है, जिस पर वह भरोसा कर सके और पर्याप्त हो (वे अपराध होने से पहले रोकने में सक्षम हों, या यदि ऐसा होता है, तो इसका पता लगाने और आरोपी को न्याय के दायरे में लाने के लिए)।

बेशक, पुलिस को ठीक से काम करना चाहिए। उन्हें सही आचरण के नियमों का पालन करना चाहिए। उन्हें धमकियों या वादों से स्वीकारोक्ति नहीं करनी चाहिए। उन्हें अधिकार के बिना किसी व्यक्ति के घर की तलाशी नहीं लेनी चाहिए। उन्हें मौके की जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं करना चाहिए।

कुल मिलाकर अधिवक्ता कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। वे पीठासीन अधिकारियों और अधिकारियों के प्रति अधिक सम्मान करते हैं, वे व्यवसायों में सबसे मेहनती वर्ग हैं। वे कठिन जीवन जीते हैं। इनका जीवन निरंतर संघर्ष का होता है। वे न्यायालय के अधिकारी हैं और न्याय प्रशासन का एक हिस्सा हैं। वे कानून के शासन को बनाए रखने की दिशा में बहुत योगदान देते हैं। एक मजबूत बार के अभाव में कानून का कोई शासन नहीं हो सकता है। कभी-कभी वे दबे-कुचले लोगों को अपने मामलों को मुक्त करने में मदद करते हैं। लेकिन उन्हें अन्याय और मनमानी से एलर्जी है। वे आते हैं और उस लोक सेवक के खिलाफ व्यक्त करते हैं जो अन्यायी है या जिसका व्यवहार उनके प्रति असभ्य है। वर्तमान मामले में शिकायत के अवलोकन से पता चलता है कि यह भ्रष्ट राजस्व अधिकारी की मिलीभगत थी, जिसे शिकायतकर्ता बुद्धि प्रकाश यादव द्वारा नोट किया गया था, सूरत राम गिरदावर (राजस्व अधिकारी) को उन व्यक्तियों से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था जो शिकायतकर्ता द्वारा तहसील के परिसर के भीतर अपने म्यूटेशन को मंजूरी देने गए थे। राजस्व अधिकारी के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था जिसमें उपखंड अधिकारी (नागरिक) ने अवैध रूप से हस्तक्षेप किया

था। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही हैं, तो उपखंड अधिकारी (नागरिक), उपायुक्त पुलिस अधीक्षक को भ्रष्टाचार को खत्म करने में शिकायतकर्ता की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय वे अराजकता में लिप्त थे, जैसा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों से स्पष्ट है। अराजकता का कर्तव्य से कोई संबंध नहीं है। अपराध का बचाव यह दलील देकर नहीं किया जा सकता कि यह उनके आधिकारिक कर्तव्य के प्रदर्शन या निर्वहन के दौरान किया गया था। जैसा कि पहले देखा गया है, किसी को भी अपने आधिकारिक कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपराध में लिप्त होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

(तेरह) *नागराज* वी। *मैसूर राज्य,* (2), यह आयोजित किया गया था :-

"यह अच्छी तरह से तय है कि शिकायत के साथ आगे बढ़ने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र शिकायत में लगाए गए आरोपों से उत्पन्न होता है, न कि आरोपी द्वारा लगाए गए आरोपों से या दर्ज किए गए सबूतों के परिणामस्वरूप मामले में अंततः क्या स्थापित होता है।

में *ज्ञानी अजमेर सिंह* बनाम *रंजीत सिंह ग्रेवाल,* (3) इसे इस रूप में आयोजित किया गया था। निम्नानुसार है :-

"यदि शिकायत में लगाए गए आरोप धारा 197 या धारा 132, आपराधिक पी.सी. के संरक्षण को आकर्षित नहीं करते हैं, तो अदालत केवल मंजूरी के अभाव में शिकायत को खारिज नहीं कर सकती है क्योंकि आरोपी लोक सेवक संभवतः सफलतापूर्वक स्थापित कर सकता है कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन या कथित निर्वहन में शिकायत की थी।

पुखराज *वी। राजस्थान राज्य और अन्य में,* (4), उनके लॉर्डशिप ने निम्नानुसार देखा: -

अदालत ने कहा, 'केवल यह तथ्य कि आरोपी ड्यूटी के निष्पादन में किए गए कृत्य का बचाव करने का प्रस्ताव रखता है, अपने आप में मंजूरी के

अभाव में मामले को खारिज करने को सही ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है. इस स्तर पर हमें केवल यह देखना है कि क्या दूसरे प्रतिवादी के खिलाफ कथित कृत्यों को उसके कर्तव्य के कथित निष्पादन में कहा जा सकता है। लेकिन बाद में न्यायिक जांच के दौरान या जांच के दौरान तथ्य प्रकाश में आए। मुकदमे में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के पाठ्यक्रम से मंजूरी की आवश्यकता स्थापित हो सकती है। मंजूरी आवश्यक है या नहीं, यह चरण से चरण पर निर्भर हो सकता है। मामले की प्रगति के दौरान यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह मुकदमे के दौरान सामग्री को रिकॉर्ड पर रखे ताकि यह दिखाया जा सके कि उसका कर्तव्य क्या था और यह भी कि किए गए कृत्य उसके आधिकारिक कर्तव्य से इतने जुड़े हुए थे ताकि धारा 197 सी.आर.पी.सी द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा को आकर्षित किया जा सके।

(चौदह) बैजनाथ *बनाम* मध्य प्रदेश *राज्य (5) मामले में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की ओर से पेश हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री इरगौर ने रेलियारिलायंस का पक्ष* रखा था, जिसमें ए. के. सरकार का अल्पमत का दृष्टिकोण था। लेकिन इस प्राधिकरण के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से अलग हैं क्योंकि यह आपराधिक दुवनियोजन से संबंधित है, हालांकि, बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार, यह निम्नानुसार देखा गया था: -

"यह एक लोक सेवक द्वारा किए गए हर अपराध नहीं है + को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 (1) के तहत मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की आवश्यकता होती है; न ही उनके द्वारा किए गए हर कार्य को भी, जबकि वह वास्तव में अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में लगे हुए हैं।

"दंड संहिता की धारा 409 के तहत जी के अभियोजन के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक नहीं थी, क्योंकि आपराधिक दुरुपयोग का कार्य उसके द्वारा नहीं किया गया था, जबकि वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों के

निर्वहन में कार्य कर रहा था या कार्य करने का इरादा रखता था और उस अपराध का लोक सेवक के रूप में जी के कर्तव्यों से कोई सीधा संबंध नहीं था और आधिकारिक स्थिति ने उसे केवल एक अवसर या एक अवसर प्रदान किया था। अपराध करने का मौका।

(पंद्रह) पश्चिम बंगाल बनाम पश्चिम बंगाल *के* राज्य के संदर्भ *में भी संदर्भ दिया गया था। बी कुमार बोस, आदि।* (6) । यह प्राधिकरण वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

(सोलह) अंत में एस। *बी. साहा और अन्य एम.एस.कोचर* (7) का हवाला दिया गया। यहां यह निम्नानुसार देखा गया था:-

"धारा 197 के तहत मंजूरी का सवाल कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है और इस पर विचार किया जा सकता है। इस सवाल पर विचार करते हुए कि अभियोजन के लिए मंजूरी की आवश्यकता थी या नहीं, अदालत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह शिकायत में लगाए गए आरोपों तक ही सीमित रहे। यह उस समय रिकॉर्ड पर सभी सामग्रियों को ध्यान में रख सकता है जब सवाल उठाया जाता है और विचार के लिए आता है।

यह प्राधिकरण शायद ही उत्तरदाताओं की मदद कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 197 के तहत मंजूरी के सवाल के संबंध में आपत्ति कार्यवाही के किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है, लेकिन किसी भी मामले में अदालत द्वारा प्रक्रिया जारी किए जाने से पहले नहीं। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों को कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति देने में गलती की, भले ही उसके द्वारा प्रारंभिक साक्ष्य दर्ज नहीं किए गए थे।

(सत्रह) उपरोक्त अधिकारियों की बारीकी से जांच से, यह स्पष्ट है कि आरोपी को प्रक्रिया जारी होने से पहले कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है: दूसरी बात यह है कि प्रक्रिया जारी होने के बाद कार्यवाही के किसी भी

चरण में मंजूरी का सवाल उठाया जा सकता है, और तीसरा, यदि कथित कृत्य और आधिकारिक कर्तव्य के बीच कोई संबंध या उचित संबंध नहीं है, तब स्वीकृति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(अठ्ठारह) जाहिर है, उत्तरदाताओं को सौंपे गए आधिकारिक कर्तव्यों और उनके द्वारा किए गए कथित कलाओं के बीच कोई संबंध नहीं है। शिकायत के अलावा कोई अन्य सामग्री नहीं है जिस पर इस स्तर पर विचार किया जाना है। शिकायत 36 फरवरी को दर्ज की गई थी। लोक अभियोजक को 29 फरवरी, 1980 को मंजूरी की आपत्ति उठाने की अनुमति दी गई थी, केवल तीन दिनों के बाद, जब शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रारंभिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसलिए यह माना जाता है कि हमले और कारावास के कथित कृत्यों और प्रतिवादियों द्वारा सौंपे गए या किए गए आधिकारिक कर्तव्यों के बीच कोई संबंध नहीं था। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया जाता है और प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है।

(उन्नीस) इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मामले का फैसला करने में आठ महीने लग गए, जो फिर से बहुत प्रशंसनीय नहीं है। यह हमारे ध्यान में आया है कि ट्रायल कोर्ट विशेष रूप से लोक सेवकों के खिलाफ शिकायतों को बहुत लापरवाह तरीके से देखते हैं। यह वांछनीय है कि ऐसी शिकायतों में जहां पीड़ित व्यक्तियों को पुलिस द्वारा भी नहीं सुना जाता है, न्यायालयों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और मामले को निर्धारित करने में कोई देरी किए बिना शिकायत के साथ तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए।

(बीस) किसी अन्य मुद्दे का आग्रह नहीं किया गया था।

(इक्कीस) पूर्वगामी कारणों से, मेरा विचार है कि मंजूरी के अभाव में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत को खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश बिल्कुल भी उचित नहीं है और परिणामस्वरूप इसे रद्द किया जाता है। विद्वान ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश

दिया जाता है।

1. एआईआर 1963 एस.सी.
2. ए.आई.आर. 1964; एस.सी. 269.
3. ए.आई.आर. 1965 पंजाब 192.
4. ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2591
5. ए.टी.आर. 1966 एस.सी. 220.
6. ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 188
7. 1979 सीआर आई एल 1367

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy